



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-20112024-258781
CG-WB-E-20112024-258781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4601]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/कार्तिक 29, 1946

No. 4601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4989(अ).—यह 30.09.2024 को हुई सुनवाई के अनुसार है।

उपर्युक्त तारीख पर सुनवाई विस्तार से सुनी गई। प्रतिवाद सहित सभी प्रस्तुतियाँ दर्ज की गईं। विभाग से कहा गया था कि वह मामले में उचित निर्णय लेने के लिए फाइल मेरे समक्ष रखे।

कथित मिल के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए, इस वर्तमान मामले में किए गए अपराध, वर्तमान मामले में कथित मिल द्वारा प्राप्त उत्तर और दी गई तारीख पर सभी पक्षों की सुनवाई के साथ-साथ रिकॉर्ड में दस्तावेज का अवलोकन किया गया, यह प्रकट होता है कि किया गया अपराध स्थापित हो गया है।

इसलिए यह आदेश दिया गया है –

- कॉनकॉर टर्मिनल (शालीमार) पर पड़े विभाग द्वारा जब्त की गई 96 गांठों को अलग किया जाना चाहिए और केवल टूटी/छेड़छाड़ की गई सीलों वाली गांठों को इस आदेश के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर मिल द्वारा अपने जोखिम और लागत पर बदला जाना है। शालीमार टर्मिनल पर कॉनकॉर के कब्जे में पड़ी शेष जब्त गांठें (अर्थात् जो सील से छेड़छाड़ के बिना या टूटी सील के बिना हैं) को एतद्वारा प्रेषण के लिए जारी किया जाता है।

2. मिल परिसर के अंदर पड़ी विभाग द्वारा जब्त की गई 144 गांठों को मिल द्वारा अपने जोखिम और लागत पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, और उसके बाद इस विभाग को सूचित करने से पहले नामित निरीक्षण एजेंसी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए।
3. मेसर्स एवरिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 2025 से शुरू होने वाले लगातार 3 (तीन) महीनों के लिए निर्धारित क्षमता के 25 प्रतिशत की कटौती करके पीसीएसओ प्राप्त करेगा।
4. उपर्युक्त जूट मिल कंपनी द्वारा इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस विभाग के माध्यम से इस प्राधिकरण के समक्ष एक अनुपालन रिपोर्ट (उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 1 और 2 पर दिए गए निर्देशों पर) प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विभाग को इस प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर संविधि और/या वित्तीय वसूली या दोनों के अनुसार और दंडात्मक उपायों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

हालांकि, मिल कंपनी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सीमा की निर्धारित अवधि अर्थात् 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी जैसा कि जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 में सन्निहित है

विभाग द्वारा इस आदेश को सभी संबंधित पक्षों को तत्काल परिचालित किया जाए।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(4)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)
ORDER

Kolkata, the 14th November, 2024

S.O. 4989(E).—This is pursuant to the hearing held on 30.09.2024.

The hearing on above mentioned date was heard at length. All the submission was recorded including counter arguments. The department was asked to place the file before me for taking appropriate decision in the matter.

Taking into account the antecedents of the alleged mill, the offence committed in this present case, the reply received by the alleged mill in the present case and upon

hearing of all sides on the given date as well as the document in the record being perused it is manifested that the offence committed is established.

Hence it is **ORDERED** –

1. The 96 bales seized by the Department lying at CONCOR terminal (Shalimar) should be segregated and only the bales with broken / tampered seals are to be replaced by the mill at their own risk and cost within 7 days from the date of issue of this order. The rest of the seized bales (i.e. which are without seal tampering or without broken seal) lying in the possession of CONCOR at the Shalimar Terminal are hereby released for dispatch.
2. The 144 bales seized by the Department lying inside the mills premises should be replaced by the mill at its own risk and cost, and thereafter it should be inspected by the designated inspection agency before dispatch under intimation to this Department.
3. M/s Averill Infrastructure Pvt. Ltd. will get PCSO by deducting 25% of the scheduled capacity for 3 (three) consecutive months starting from January 2025.
4. A compliance report (on directives at Sl. No. 1 and 2 as above) should be submitted by the aforesaid jute mill company before this authority through this Department, within 15 days from the date of issue of this Order, failing which the Department should appear before this authority praying for further punitive measures as per statute and / or financial recovery or both.

However, the mill company will be of liberty to file an appeal before the competent authority as embodied in Jute & Jute Textiles Control Order, 2016 within the prescribe period of limitation i.e. 30 days.

Let this order be circulated to all the concerned parties' by the department forthwith.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(4)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner